एक नई सुबह की शुरुआत

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- सऊद अल-सती (भारत में सऊदी अरब के राजदूत)

16 फरवरी, 2019

"भारत और सऊदी अरब प्रभावशाली रूप से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं।"

अप्रैल 2016 में, दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक के नेतृत्व में, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने विजन-2030 के रूप में खुद के लिए एक लक्ष्य और एक प्रतिज्ञा निर्धारित की थी। सऊदी नागरिक एक जीवंत समाज, संपन्न अर्थव्यवस्था और महत्वाकांक्षी राष्ट्र के निर्माण की दिशा में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के साथ सतत् विकास के लिए केंद्र बिंदु बन गया है। अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास और रसद कार्यक्रम के माध्यम से 1.6 मिलियन नई नौकरियों का सृजन करने के लिए अगले दशक में निजी निवेशों में 427 बिलियन डॉलर को आकर्षित करने के उद्देश्य से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की पूरी नींव पूर्व के तेल युग से आगे बढ़ रही है।

सुधारों द्वारा संचालित

विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस-2018 रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब ने जुलाई, 2017 तक मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र के देशों के बीच सबसे अधिक व्यापार सुधारों की स्थापना की है। अपने मंच मेरास के साथ, किंगडम में कारोबार शुरू होने के लिए अब केवल एक कदम और एक दिन की आवश्यकता है। सीमा शुल्क निकासी और आयात तथा निर्यात प्रक्रियाओं के लिए सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म फसाह (Fasah) भी लॉन्च किया गया है।

डूइंग बिजनेस, 2019 रिपोर्ट ने सऊदी अरब को जी-20 के भीतर चौथे सबसे बड़े सुधारक या रिफॉर्मर के रूप में स्थान दिया है। 2018 में, सऊदी अरब ने वर्ष-दर-वर्ष 127% की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वृद्धि देखी है। जुलाई, 2018 में सऊदी अरब के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्वानुमान में वृद्धि के साथ सऊदी अरब के बढ़ते कदम पर वैश्विक विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया है।

किंगडम का निर्माण बाजार वर्ष 2016 में 45.33 बिलियन डॉलर से वर्ष 2025 में 96.52 बिलियन डॉलर को छूने के लिए तैयार है। इसके अलावा, तीन गीगा-प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट न्यूम, किदिया एंटरटेनमेंट सिटी और रेड सी टूरिज्म प्रोजेक्ट शामिल है। 2018 में, हमने सऊदी अरब को वैश्विक नवाचार हब बनाने के उद्देश्य से डिजिटल विचारों के लिए एक राष्ट्रीय पहल, फेकराटेक शुरू की। सऊदी बौद्धिक संपदा प्राधिकरण भी नवाचार और उद्यमिता पर निर्मित एक उन्नत ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में सऊदी अरब को बदलने की दिशा में काम कर रहा है।

परिवहन परियोजनाओं में 100 बिलियन डॉलर का नियोजित निवेश अगले दशक में भी जारी रहेगा क्योंकि हम रेलवे प्रणाली का विस्तार करेंगे और रियाद, जेद्दा, मक्का और मदीना में नई हल्की रेल परिवहन परियोजनाएँ शुरू करेंगे। मक्का में पवित्र मस्जिद और मदीना में पैगंबर की मस्जिद के भव्य विस्तार ने लाखों उपासकों को समायोजित करने की उनकी क्षमता में वृद्धि की है। विजन-2030 के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में 2030 तक हर साल 30 मिलियन उमराह कलाकारों के स्वागत की हमारी क्षमता को बढ़ाना, उनके अनुभव में सुधार करना और इसे और समृद्ध करना शामिल है।

चूंकि देश की अधिकांश आबादी 30 वर्ष से कम है, इसलिए शिक्षा भी विजन'2030 का एक प्रमुख घटक है। दशकों से, सऊदी अरब की शिक्षा प्रणाली आश्चर्यजनक परिवर्तन से गुजरी है। किंगडम से उदार छात्रवृत्ति के कारण बड़ी संख्या में सऊदी छात्र विदेशों में अध्ययन करते हैं। 2030 तक, किंगडम का इरादा अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 200 में कम से कम पांच सऊदी विश्वविद्यालयों को शामिल करना है। शिक्षा सुधारों से महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई है और कार्यबल में भी भागीदारी बढ़ी है।

अरब और इस्लामी दुनिया के केंद्र में किंगडम के साथ, सऊदी धरती पर हो रहे बदलाव पूरे अरब क्षेत्र के लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहे हैं। सऊदी अरब क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवाद का मुकाबला करने और 2018 में रियाद में इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच हस्ताक्षर किया गया ऐतिहासिक शांति समझौता देश में शांति स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। विकास और स्थिरता के लिए हमारी आम खोज में, सऊदी अरब भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। हमारे संबंध तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से जुड़े हुए हैं। चाहे बात व्यापार, विज्ञान, कला, साहित्य, भाषाओं की हो जाये या हमारी सभ्यताओं के बीच आदान-प्रदान की, हमारे संबंध वास्तव में मजबूत रहे हैं। भारत हमारे लिए एक विशेष स्थान रखता है। लगभग 3 मिलियन भारतीय किंगडम में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय का निर्माण करते हैं। भारत पिछले दो वर्षों के दौरान अपने 1,36,020 के हज कोटे में लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज कराते हुए 1,75,025 तक के आंकड़े तक पहुँच गया है। भारत और सऊदी अरब के पास आज पहले की तुलना में अधिक अवसर हैं। 2017-18 के लिए द्विपक्षीय व्यापार, जो 27 बिलियन डॉलर से अधिक था, सऊदी अरब और भारत के लिए नए क्षेत्रों: जैसे-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), स्वास्थ्य देखभाल, रक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में भी तेजी लाएगा। भारत कार्बनिक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश की बड़ी संभावनाओं के साथ किंगडम की पसंदीदा सूची में शीर्ष देशों में से एक है।

सहयोग का विस्तार

दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी को भी नया आधार मिल रहा है। अक्टूबर, 2018 तक, सऊदी अरामको के पास भारतीय कंपनियों के साथ सामग्री-सेवा में लगभग 2 बिलियन डॉलर का व्यापार है और तेल की आपूर्ति, विपणन और शोधन से लेकर पेट्रोकेमिकल और स्नेहक तक भारत की मूल्य श्रृंखला में निवेश करना इसकी वैश्विक डाउनस्ट्रीम रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

महाराष्ट्र में रत्नागिरि में 44 बिलियन डॉलर की एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स, सऊदी अरब, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) द्वारा विकसित किया जा रहा है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) से मिलकर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (PSU) का एक संघ अभी तक एक और मील का पत्थर साबित हुआ है।

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नवंबर, 2018 में जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के मामले में ठोस पहल को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च-स्तरीय तंत्र स्थापित करने पर सहमति भी व्यक्त की थी।

मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, सऊदी अरब और भारत के पास अपने क्षेत्रों के भविष्य को सवारने में सहयोग करने का एक ऐतिहासिक अवसर है, जिससे समृद्धि और भरोसे से भरे बेहतर कल का निर्माण हो पाएगा। हमारी संबंधित शक्तियों के संयोजन से हमारे लोगों और क्षेत्रों के लाभ के लिए अनंत संभावनाओं और उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त होगा। क्राउन प्रिंस की भारत की आगामी राजकीय यात्रा दोनों मित्र देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने का एक और ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है।

GS World टीम...

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

संदर्भ

- पिछले वर्ष विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में भारत ने 23 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया था।
- विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर, 2018 को वैश्विक कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट जारी की थी। भारत की यह रैंकिंग अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।
- दस में से 8 मानकों में भारत की स्थिति सुधरी है।
- दरअसल, पिछले वर्ष 190 देशों की सूची में भारत को पहली बार शीर्ष 100 में जगह मिली थी।
- पिछले 2 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है।
- दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक फर्स्ट है। इससे पहले साल 2014 में भारत 6वें स्थान पर था।

क्या है?

- ईज ऑफ डूइग बिजनेस से अर्थ है कि देश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है।
- कारोबार के नियामकों और उनके नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जाता है कि किसी देश में ये कितनी आसान या मुश्किल हैं।
- डूइग बिजनेस रैंकिंग डिस्टेंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ) के आधार पर तय किया जाता है और यह स्कोर दिखाता है कि वैश्विक मानकों पर अर्थव्यवस्था कारोबार के मामले में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
- वर्ष 2018 में भारत का डीटीएफ स्कोर पिछले साल के 60.76 से बढ़कर 67.23 पर आ गया है।

दुर्लभ उपलब्धि

- भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊंची छलांग निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाई थी, जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- इस बार कारोबार सुगमता रैंकिंग में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा। उसके बाद क्रमश: सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का स्थान था।
- सूची में अमेरिका आठवें, चीन 46वें और पाकिस्तान 136वें स्थान पर रहा। विश्व बैंक ने इस मामले में सबसे अधिक सुधार करने

वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दसवें स्थान पर रखा।

- भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है जो डूइंग बिजनेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में किये गये सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है।

कैसे तय होती है यह रैंकिंग?

- भारत ने वर्ष 2003 से अब तक 37 बड़े सुधार लागू किए हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 2017 में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था।
- रिपोर्ट में किसी कारोबार को शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना और दिवालिया शोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' इंडेक्स जारी किया जाता है।
2. 2018 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का 77वां स्थान रहा था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements-

1. Ease of doing business index is published by world economic forum.
2. India's rank 77th in published 2018 Ease of doing business Index.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: सऊदी अरब के बदलते स्वरूप को देखते हुए भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए? चर्चा कीजिए।

Q. After seeing a transforming Saudi Arab, which type of politics should be adopted to strengthen the relation of India and Saudi Arab. Discuss.

(250 Words)

नोट : 15 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।